उपलब्ध रियायतों के लिए विश्वास उत्पन्न करने में सहायता करेगा ।

(ख) एक व्यापक अधिनियम, जो कि केवल कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए ही नहीं है बल्कि ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए है, विचार के, अग्रवती चरण में है ।

कपड़े का उत्पादन

266. **श्री मीर्जा इर्शादबेग एवबबेग** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विभिन्न कपड़ा मिलों द्वारा प्रति वर्ष कितने कपड़े का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) प्रति वर्ष किस-किस किस्म का कपड़ा कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान विदेशों से कपड़े की खरीद के लिये कितने आर्डर प्राप्त हुए और देश में कपड़े की वार्षिक खपत कितनी है ;

(घ) पिछले दो वर्ष के दौरान कपास तथा रेयन धागे की दरों के संबंध में क्या स्थिति रही है ;

(ङ०) क्या खुले बाजार में कपड़े की दरों में गिरावट आई है ; और

(च) उन कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान लाभ अर्जित किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में **राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर)** : (क) 1983-84 के दौरान देश में वस्त्र मिलों द्वारा कपड़े के कुल उत्पादन का भुगतान 3933 मिलियन मीटर है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित सूती कपड़े की किस्में तथा मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिये) ।

(ग) विदेशों से कपडे की खरीद के संबंध में प्राप्त हुये आर्डरों की स्थिति को मानिटर नहीं किया जाता हैं । 1983 के लिये प्रति व्यक्ति खपत 13.68 मीटर अनुमानित की गई हैं ।

(घ) 18 मार्च, 1983 की तुलना में जून, 1984 में औसत बाजार कीमतें काटन हेक यार्न के लिये 6.2 प्रतिशत, काटन कोन यार्न के लिये .2 तथा विस्कोस के फिलामेंट यार्न के लिये 7.1 बढ़ी ।

(ङ) जनवरी, 1983 से जून, 1984 के मध्य तक की अवधि में मिलों से सूती कपड़ों की थोक बिक्री कीमतों में सूचकांक में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हथकरघा तथा विद्युत करघा कपड़े की कीमतों में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सिल्क तथा आर्ट सिल्क कपड़े की कीमतों में 2.6 प्रतिशत की कमी हुई ।

(च) गत दो वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाली कपड़ा मिलों की संख्या के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

(आंकड़े मिलियन वर्ग मी० में)

	निर्यातित कपड़े की मात्रा		
किस्म	1981	1982	1983
ड्रिल्ज एण्ड डैनीमस	9.36	3.63	5.96
शर्टिंस	3.81	6.08	1.96

किसम	निर्यातित कपड़े की मात्रा		
	1981	1982	1983
लट्ठा	27.05	3.8	8.60
टविल एंड शैटीन	27.02	17.88	14.41
फैलनेलेट	5.74	2.09	2.50
डाम्सटिक्स	8.75	6.05	9.61
वपथत्य एंड मूल्ज	13.90	2.47	3.18
शार्टिग्स	119.32	75.87	149.67
साड़ियां एंड धोतियां	1.85	1.60	2.36
कैनवास	6.05	7.85	5.19
अन्य	48.85	11.80	9.17
योग :	271.70	199.16	272.61

प्रोत : सती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ।

Damage to Records of STC due to Fire

267. SHRI J. P. GOYAL: WiH the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a fire broke out in the Chandralok Building, Janpath, New Delhi on the 1st June, 1984 in which valuable records of the State Trading Corporation were burnt;

(b) what was the cause of the fire;

(c) what are the details of the damage caused to State Trading Corporation by the fire; and

(d) whether any sabotage is suspected behind this incident?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OP SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) A fire broke out in the Chandralok Building, Janpath, New Delhi o_n 1-6-84. No valuable records were burnt.

(b) CID, Delhi Police is investigating into the causes of the fire.

(c) Office partition walls, false ceilings, electrical fittings, furnitures, air conditioners, typewriters and Telephones etc. costing Rs. 30.40 lakhs approximately have been damaged by the fire.

(d) whether there was any sabotage behind this incident will be known only after completion of the investigation.

Funds provided by IDBI to State

268. SHRi J. P. GOYAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Industrial Development Bank of India provides funds to the State Financial Corporations for promoting small business ventures under self-employment scheme;

(b) if so, what are the details in' this respect for the last three years;

(c) whether IDBI has communicated certain guidelines to the State Financial Corporations in this regard, and if so, what ar_e the salient features thereof;

(d) whether it has come to the notice of the IDBI that most of the State Financial Corporations could not properly utilise the sanctioned funds; if so, what are the details in this regard; and

(e) what measures are proposed to be taken to ensure proper utilisation of the funds by the State Financial Corporations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): (a) The Industrial Development Bank of India (IDBI) extends assistance